Utilisation of Water

1766. SHRI DEBABRATA BISWAS Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the quantum of economically utilisable water available in the country; and

(b) what efforts being made by Government for the development of economically utilisable water for different purposes?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) Out of 4000 cubic kilometres of annual precipitation (snow and rainfall) received by the country, the utilisable quantity of water assessed at present is 1140 cubic kilometres, including 450 cubic kilometres of annual replenishable ground water.

(b) The state Governments are implementing major, medium and minor irrigation schemes for increased utilisation of utilisable water. A total of 263 major irrigation projects and 1104 medium irrigation projects have been taken up so far all over the country in addition to a large number ofwell/tube well irrigation work tanks and other minor irrigation works. Out of these 84 major projects and 778 medium projects have been completed so far. In addition, other measures taken for development of economically utilisable water for different purposes include water-shed development programmes and Command Area Development Programme undertaken since 1974-75. In the light of the National water Policy adopted in September, 1987, establishment of river basin organisations for systematic coordination and management of the river basins has also been planned.

उत्तर प्रदेश की नल कप परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1767. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार उन शर्तों का पालन कर रही है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सम्बद्ध साख समझौतों (साख संख्या 1004 आई एन, 1332 आई एन और 8 आई एन) में उल्लिखित वित्तीय सहायता के उपयोग के संबंध में शर्तें अनुपत्र में दी गयी हैं [**देखिये**] परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं० 32)

(ख) चूंकि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सार्वजनिक नलकूप परियोजनाएं समाप्त कर दी गयी हैं, इसलिए इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इन शर्तों के पालन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

1768. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **जल ससाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।